

सांसद रजनीताई पाटील ने की मनोज जरांगे पाटील से मुलाकात

केज, १८ जून

मराठा आरक्षण आंदोलन के संघर्षशील नेता मनोज दादा जरांगे पाटील से आज कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री और सांसद रजनीताई पाटील, पूर्व मंत्री अशोक पाटील ने अंतरवाली सराई गांव में शिष्यचार्चा घंटे की। इस अवसर पर उन्होंने उनका सत्कार करते हुए शुभकामनाएं भी दीं।

इस दौरान युवा नेता अदित्य पाटील, कांग्रेस जिला अध्यक्ष राहुल सोनवणे, तातुका अध्यक्ष महेश बेंद्रे, श्रीनिवास बेंद्रे सहित कई



कार्यकर्ता मौजूद हो।

भंटे के दौरान मराठा आरक्षण के मुद्दे सहित जिले के अन्य सामाजिक विषयों पर भी विस्तृत

चर्चा हुई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों ने भाग लिया और चर्चा को गंभीरता से सुना।

# छत्रपति मल्टीस्टेट में जमा रारी नहीं मिलने से पुष्ट की आत्महत्या, बैंक के सामने लगाया फारी का फटा

गेवराई / बीड ,प्रतिनिधि  
छत्रपति मल्टीस्टेट सहकारी संस्था में जमा रकम न मिलने से मानसिक तनाव झेल रहे हैं। एक युवा किसान सुरेश आत्माराम जाधव (उम्र ४०) ने संस्था की गेवराई शाखा के सामने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस घटना से पूरे शहर में हड़कंप मच गया है। घटना का पूरा विवरण मृतक की पत्नी कविता सुरेश जाधव (३५) ने पुलिस में दी गई शिकायत में बताया कि उनका परिवार कृषि पर आधारित है। उनकी एक बेटी साक्षी (२१) और बेटा शुभम (१८) पढ़ाई कर रहे हैं। बच्चों के भविष्य और शिक्षा हेतु उन्होंने वर्ष २०२० से अब तक छत्रपति मल्टीस्टेट की गेवराई शाखा में कुल ११ लाख ५० हजार रुपये की सावधि जमा करवाई थी।



लेकिन पिछले दो वर्षों से संस्था बार-बार टालमटोल कर रही थी। किमी आज पैसे मिलेंगे, तो कभी कल आना कहकर उनका विश्वास तोड़ा गया। छह महीने पहले जब सुरेश जाधव ने आत्महत्या की चेतावनी दी थी, तब चेयरमैन संतोष उर्फ नाना भंडारी ने केवल २.५ लाख रुपये लौटाएं। और बाकी ९ लाख दो माह में देने का वादा किया था, जो कभी पूरा नहीं हुआ।

घटनाक्रम  
दिनांक १७ जून को सुरेश जाधव, उनकी पत्नी और बांदों बच्चे फिर से संस्था पहुंचे लेकिन इस बार शाखा प्रबंधक ने न केवल पैसे देने से इनकार किया, बल्कि सुरेश जाधव को अपमानित करते हुए शाखा से बाहर निकाल दिया।

मानसिक रूप से टूट चुके सुरेश जाधव ने अगले ही दिन १८ जून को सुबह ३ बजे छत्रपति मल्टीस्टेट शाखा के बाहर फांसी लगाकर दान दे दी।

आत्महत्या से पहले उन्होंने शाखा प्रबंधक ज्योती को छाहासएप मैसेज भेजकर लिखा: मेरे बच्चों की पढ़ाई बर्बाद करने के लिए धन्यवाद। मैंने बार-बार गुहार लगाई, लेकिन आपने पैसे नहीं दिए। अब मैं आपके सामने आत्महत्या कर रहा हूं। यह संदेश संतोष भंडारी और भंडारी दादा तक पहुंचा दें।

परिजनों का आक्रोश और पुलिस कार्रवाई  
घटना के बाद गुस्साए परिजनों ने साफ कराया कि जब तक चेयरमैन संतोष भंडारी को गिरफ्तार नहीं से पूछे तो पता चलेगा कि कितने

लोगों की जमा राशि वर्षों से अटकी हुई है, और प्रशासन मूकदर्शक बना रहता है।

स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि

ऐसे संस्थानों की ऑडिट रिपोर्ट सार्वजनिक करें,

निवेशकों के अधिकारों की रक्षा के लिए विशेष प्रक्रोष बनाएं,

और संस्थागत लेवल पर फ्रॉड रोकने के लिए ठिक्का के समकक्ष निगरानी व्यवस्था बनाई जाए।

एक गरीब किसान को बार-बार अपमानित कर आत्महत्या की कगार पर ले जाना, सिर्फ वित्तीय धोखा नहीं, मानवीय अपाधा है। सरकार को इस घटना का संज्ञान लेकर छत्रपति मल्टीस्टेट जैसी संस्थाओं पर न तो आरबीआई की स्पष्ट निगरानी होती है और न ही इनके चेयरमैन व प्रबंधकों पर जवाबदेही सुनिश्चित की जाती है।

सहकारी संस्थाओं में अक्सर नेता, रसूखदार व्यक्ति और स्वघोषित समाजसेवी बैठे होते हैं। सरकार को इस घटना का संज्ञान लेकर छत्रपति मल्टीस्टेट जैसी संस्थाओं की तत्काल जांच और नियंत्रण में लेना चाहिए।

## नितीन गडकरी ने की बड़ी घोषणा: ३००० रुपये में मिलेगा FASTag आधारित 'वार्षिक पास'



दिल्ली

१५ अगस्त २०२५ से लागू होगा वार्षिक FASTag पास।

३००० रुपये में मिलेगा यह पास, जिसकी वैधता एक वर्ष या २०० बार राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रा करने तक-जो भी पहले पूरा हो।

यह योजना के बल निजी, गैरव्यावसायिक वाहन जैसे कार, जीप, वैन आदि के लिए है।

नियमित राजमार्ग यात्रियों के लिए आसान और किफायती सामाधान टोल शुल्क का पूर्वभुगतान, जिससे

टोल प्लाजा पर रुकावट और विवाद कम होंगे।

६० किमी के भीतर बारबार टोल का झंझट खत्म होगा।

कुछ मामलों में यह पास मौजूदा मासिक पास (प्रति माह ३४०) से हजारों रुपये सस्ता पड़ेगा।

'राजमार्ग यात्रा' (Rajmarg Yatra) ऐप, NHAI और MoRTH की वेबसाइटों पर एक विशेष लिंक जल्द ही एक्टिवेशन और रीन्यूअल के लिए उपलब्ध होगा।

अज्ञात टोल प्लाजाओं में

बोमबायर हटाने के प्रयास

ANPR (स्वचालित नंबरप्लेट पहचान) वाले टोल सिस्टम की शुरुआत भी प्रस्तावित है।

नितीन गडकरी द्वारा अनुरूपित यह F-STag-आधारित वार्षिक पास योजना, ३००० रुपये में, १५ अगस्त २०२५ से लागू होगी। निजी वाहन मालिकों को न केवल आर्थिक बचत होगी, बल्कि टोल प्लाजा पर लगाने वाली लाइन और देरी से भी निजात मिलेगी। ANPR टेक्नोलॉजी से इसे और भी सुविधाजनक बनाया जाएगा।

जुना बाजार कोतवाली वेस से छत्रपति शिवाजी महाराज चौक तक सड़क का काम तुरंत शुरू करें, नहीं तो आंदोलन होगा-अमरजान पठान



बीड / प्रतिनिधि

बीड शहर के जुना बाजार कोतवाली वेस से लेकर बलभीम चौक, करंजा रोड और राजुरी वेस

होते हुए छत्रपति शिवाजी महाराज चौक तक की सड़क की हालत बेहद खराब हो चुकी है। इन सड़कों पर बड़े-बड़े गड्ढे बैठे होते हैं, जिससे आम जनता को आवागमन में भारी परेशानी हो रही है।

यह मार्ग शहर के बीच से गुजरने वाला प्रमुख व्यापारिक रास्ता है, जहाँ प्रतिदिन बड़ी संख्या में नागरिक और व्यापारी आते हैं।

बरसात के चलते सड़कों पर पानी भर जाता है और दुर्घटनाओं का खतरा भी लगातार बना हुआ है। इसी समस्या को लेकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) ने बीड नगर परिषद के उपमुख्य आधिकारी कार्यालय के गढ़ों में बेशरम के पौधे लगाकर शांतिपूर्ण आंदोलन किया जाएगा।

यह चेतावनी बीड नगर परिषद और जिलाधिकारी कार्यालय को सौंपे गए ज्ञापन में दी गई है। इस अवसर पर मनसे के जिलाधिकारी आशा कुटे, जिला उपाध्यक्ष कल्पना कवठेकर, सदाशिव बिडवे, शहराध्यक्ष अमरजान पठान समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे।

## हिंदी अनिवार्य नहीं, मराठी ही रहेगी जरूरी भाषा: दादा भुसे का स्पष्टीकरण

मुंबई, १८ जून | रिपोर्ट: जमीर क़ाज़ी

राज्य सरकार पर यह आरोप लगने के बाद कि पहली से पांचवीं कक्षा तक हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में थोपा जा रहा है, राज्य के शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे ने स्पष्ट किया कि मराठी भाषा सभी स्कूलों में अनिवार्य रहेंगी, जबकि हिंदी सहित अन्य भारतीय भाषाएँ ऐचिक (वैकल्पिक) रहेंगी।

मंत्री दादा भुसे ने बुधवार को मीडिया से बात करते हुए कहा कि राज्य पाठ्यक्रम आराखड़ा शालेय शिक्षण २०२४ के अनुसार, मराठी और अंग्रेजी माध्यम की शालाओं में पहली से पांचवीं तक मराठी को मांग की तर

के रूप में पढ़ाया जाएगा। लेकिन अगर कोई छात्र हिंदी की

# बीड़ ज़िले में बालविवाह रोकने के लिए प्रशासन की नई पहले और योजनाएं

बीड़ ज़िले में बालविवाह जैसी समाजिक बुराई को रोकने के लिए ज़िला प्रशासन द्वारा विभिन्न विभागों के माध्यम से कई प्रतिबंधात्मक उपाय और जनजागृति कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य बालिकाओं को शिक्षा और सुरक्षित भविष्य देना है।

शिक्षा विभाग के हफ़्लें:

हर स्कूल में हर सोमवार बालविवाह विरोधी शपथ दिलवाला जाएगा।

नुक़़ड़ नाटक, निबंध स्पर्धा, रंगोली प्रतियोगिता जैसी गतिविधियों के माध्यम से गांवों में जनजागृति की जाएगी।

अगर कोई छात्रा (७वीं से १२वीं तक) १५ दिनों से ज्यादा स्कूल से

अनुपस्थित रहती है, तो उसकी जानकारी अॅनलाइन भरकर संबंधित कार्रवाई की जाएगी।

महिला व बाल विकास विभाग:

DTF की बैठक अब हर हफ़्ले होगी (हफ़्ले ३ महीने में एक बार होती थी)।

पिछले वर्ष रोके गए २४५ बालविवाह मामलों का समाजिक और अधिक सर्वेक्षण किया जाएगा, ताकि इसके पछाँ के कारणों को समझा जा सके।

बालविवाह रोकने में योगदान देने वाले ग्रामसेवक और आंगनवाड़ी सेविकाओं को पालक मंत्री के हाथों



जिन लड़कियों ने बालविवाह से

बचकर अपनी पढ़ाई पूरी की, उन्हें भी ज़िला स्तर पर पुरुषकार देकर सम्मानित किया जाएगा।

पंचायत विभाग की हफ़्लें:

बालविवाह से बची हुई लड़की का दोबारा विवाह न हो, इसके लिए सरकारी कर्मचारियों को उसके लिए पालक अधिकारी नियुक्त किया जाएगा।

सभी तउझउ और डुड़ज़ु सदस्यों को बालविवाह रोकने संबंधी संदेश (खेत) लिखे जाएं।

FIR की संख्या बढ़ाने के लिए ग्रामविकास, पुलिस और अन्य विभागों में समन्वय किया जाएगा।

हर ग्रामसभा में बालविवाह पर जनजागृति की जाएगी और गट विकास अधिकारी की हर १५ दिन की बैठक में इस विषय पर समीक्षा की जाएगी।

पुलिस विभाग की भूमिका:

बालविवाह के मामलों में कड़ी कार्रवाई और अधिक ऋखर दर्ज करने के लिए अन्य विभागों से तालमेल बनाया जाएगा।

अन्य महत्वपूर्ण कदम:

सरकारी संस्थानों की दीवारों पर बालविवाह रोकने संबंधी संदेश (खेत) लिखे जाएं।

उपरिभागीय अधिकारी और तहसीलदार हर महीने बालविवाह पर

किए गए कार्यों की समीक्षा करेंगे और त्रैमासिक बैठक में रिपोर्ट पेश करेंगे।

थो बॉल खेल को बालिकाओं के बीच बढ़ावा दिया जाएगा।

जोखिम में रह रही बालिकाओं की पहचान कर, उन्हें सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ा जाएगा।

बालविवाह रोकने में अच्छा काम करने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों को सम्मानित किया जाएगा।

यह योजनाएं बालिकाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के साथ ही समाज को बालविवाह जैसी कुप्रथा से मुक्त करने की दिशा में एक अहम कदम हैं।

## अल्पसंख्यक संस्थाओं को डिजिटल प्रमाणपत्र की शर्त से मिले राहत-कैसर आज़ाद शेख की मांग

परतूर / एम. एल. कुरेशी

महाराष्ट्र राज्य में जुलाई २०१७ से पहले अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त कर चुकी शैक्षणिक संस्थाओं को अब आपले सरकार पोर्टल के माध्यम से अॅनलाइन डिजिटल स्वाक्षरी (हस्ताक्षर) युक्त प्रमाणपत्र अनिवार्य रूप से प्राप्त करने के आदेश अल्पसंख्यक विकास विभाग द्वारा जारी किए गए हैं।

शासन निर्णय में उल्लेख किया गया

है कि जुलाई २०१७ के पूर्व ऑफलाइन अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त शालाओं और संस्थाओं की विस्तृत जानकारी शासन के पास उपलब्ध नहीं है। इसलिए यह जानकारी सुमात्रा से प्राप्त करने हेतु उन सभी संस्थाओं को छह माह की अवधि में डिजिटल प्रमाणपत्र प्राप्त करना आवश्यक किया गया है।

इस निर्णय का विरोध करते हुए

महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमिटी के

लिए वर्ष रोके गए २४५ बालविवाह मामलों का सामाजिक और आर्थिक सर्वेक्षण किया जाएगा, ताकि इसके पछाँ के कारणों को समझा जा सके।

इस निर्णय का विरोध करते हुए

महाराष्ट्र कांग्रेस कमिटी के

प्रतिवाइर जैसी विभागों के माध्यम से अॅनलाइन डिजिटल स्वाक्षरी अवधि के अन्तर्गत जानकारी सुमात्रा से प्राप्त करने हेतु उन सभी संस्थाओं को छह माह की अवधि में डिजिटल प्रमाणपत्र प्राप्त करना आवश्यक किया गया है।

इस निर्णय का विरोध करते हुए

महाराष्ट्र कांग्रेस कमिटी के

प्रतिवाइर जैसी विभागों के माध्यम से अॅनलाइन डिजिटल स्वाक्षरी अवधि के अन्तर्गत जानकारी सुमात्रा से प्राप्त करने हेतु उन सभी संस्थाओं को छह माह की अवधि में डिजिटल प्रमाणपत्र प्राप्त करना आवश्यक किया गया है।

इस निर्णय का विरोध करते हुए

महाराष्ट्र कांग्रेस कमिटी के

प्रतिवाइर जैसी विभागों के माध्यम से अॅनलाइन डिजिटल स्वाक्षरी अवधि के अन्तर्गत जानकारी सुमात्रा से प्राप्त करने हेतु उन सभी संस्थाओं को छह माह की अवधि में डिजिटल प्रमाणपत्र प्राप्त करना आवश्यक किया गया है।

इस निर्णय का विरोध करते हुए

महाराष्ट्र कांग्रेस कमिटी के

प्रतिवाइर जैसी विभागों के माध्यम से अॅनलाइन डिजिटल स्वाक्षरी अवधि के अन्तर्गत जानकारी सुमात्रा से प्राप्त करने हेतु उन सभी संस्थाओं को छह माह की अवधि में डिजिटल प्रमाणपत्र प्राप्त करना आवश्यक किया गया है।

इस निर्णय का विरोध करते हुए

महाराष्ट्र कांग्रेस कमिटी के

प्रतिवाइर जैसी विभागों के माध्यम से अॅनलाइन डिजिटल स्वाक्षरी अवधि के अन्तर्गत जानकारी सुमात्रा से प्राप्त करने हेतु उन सभी संस्थाओं को छह माह की अवधि में डिजिटल प्रमाणपत्र प्राप्त करना आवश्यक किया गया है।

इस निर्णय का विरोध करते हुए

महाराष्ट्र कांग्रेस कमिटी के

प्रतिवाइर जैसी विभागों के माध्यम से अॅनलाइन डिजिटल स्वाक्षरी अवधि के अन्तर्गत जानकारी सुमात्रा से प्राप्त करने हेतु उन सभी संस्थाओं को छह माह की अवधि में डिजिटल प्रमाणपत्र प्राप्त करना आवश्यक किया गया है।

इस निर्णय का विरोध करते हुए

महाराष्ट्र कांग्रेस कमिटी के

प्रतिवाइर जैसी विभागों के माध्यम से अॅनलाइन डिजिटल स्वाक्षरी अवधि के अन्तर्गत जानकारी सुमात्रा से प्राप्त करने हेतु उन सभी संस्थाओं को छह माह की अवधि में डिजिटल प्रमाणपत्र प्राप्त करना आवश्यक किया गया है।

इस निर्णय का विरोध करते हुए

महाराष्ट्र कांग्रेस कमिटी के

प्रतिवाइर जैसी विभागों के माध्यम से अॅनलाइन डिजिटल स्वाक्षरी अवधि के अन्तर्गत जानकारी सुमात्रा से प्राप्त करने हेतु उन सभी संस्थाओं को छह माह की अवधि में डिजिटल प्रमाणपत्र प्राप्त करना आवश्यक किया गया है।

इस निर्णय का विरोध करते हुए

महाराष्ट्र कांग्रेस कमिटी के

प्रतिवाइर जैसी विभागों के माध्यम से अॅनलाइन डिजिटल स्वाक्षरी अवधि के अन्तर्गत जानकारी सुमात्रा से प्राप्त करने हेतु उन सभी संस्थाओं को छह माह की अवधि में डिजिटल प्रमाणपत्र प्राप्त करना आवश्यक किया गया है।

इस निर्णय का विरोध करते हुए

महाराष्ट्र कांग्रेस कमिटी के

प्रतिवाइर जैसी विभागों के माध्यम से अॅनलाइन डिजिटल स्वाक्षरी अवधि के अन्तर्गत जानकारी सुमात्रा से प्राप्त करने हेतु उन सभी संस्थाओं को छह माह की अवधि में डिजिटल प्रमाणपत्र प्राप्त करना आवश्यक किया गया है।

इस निर्णय का विरोध करते हुए

महाराष्ट्र कांग्रेस कमिटी के

प्रतिवाइर जैसी विभागों के माध्यम से अॅनलाइन डिजिटल स्वाक्षरी अवधि के अन्तर्गत जानकारी सुमात्रा से प